डॉ. मोहन यादव के सीएम के रूप में 2 वर्ष

आत्मविश्वास से लबरेज डॉ. मोहन यादव की उपलब्धियां और आगामी लक्ष्य

मुख्यमंत्री के रूप में दो वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा करने वाले डॉ मोहन यादव अब और अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आने लगे हैं. कार्यभार संभालने के बाद से ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस राज्य के विकास को नयी रफ्तार देने में जुटे हुए हैं.

डॉ. मोहन यादव अपने सार्वजनिक संबोधनों के दौरान यह कहने में कोई संकोच नहीं दिखाते हैं कि वे मोदी और शाह के मार्गदर्शन और दिशानिर्देशों के अनुरूप इस राज्य का विकास डबल इंजन की सरकार के माध्यम से कर रहे हैं. वे अपनी प्राथमिकताओं में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करते हुए दिख रहे हैं. दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार की ओर से जारी किए गए आकड़े भी कमोवेश इसी ओर संकेत करते हैं. मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाकर उनके समझ इस राज्य के विकास पुरुष के रूप में दर्ज होने का सुनहरा अवसर भी मौजूद है.

13 दिसंबर 2023 को जब डॉ मोहन यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली, तब उनके समक्ष चुनौतियां भी कम नहीं थीं.

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्थान लिया था, जो इस पद पर लगभग अठारह वर्षों तक आसीन रहे. राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि डॉ मोहन यादव को नया शासन नयी व्यवस्था के साथ चलाने में अनेक कठिनाइयां आ सकती थीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने तुलनात्मक रूप से कम बात कर काम पर ज्यादा फोकस करने की नीति पर चलते हुए सकारात्मक नतीजे दिए.

इन दो वर्षों के दौरान डॉ मोहन यादव ने न सिर्फ राजनैतिक स्तर पर चुनौतियों

का डटकर मुकाबला किया, बल्कि प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाया. उन्होंने अपने सहयोगी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बेहतर ढंग से तालमेल बिठाया, तो प्रदेश संगठन के साथ भी बेहतर कदमताल किया. उन्होंने बिहार और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में सैकड़ों चुनावी सभाएं लीं. लगभग सभी सीटों पर नतीजे भी इन दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में

आए. डॉ मोहन यादव ने सभाओं में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ ही मध्यप्रदेश सरकार में किए गए कामों को गिनाया.

डॉ मोहन यादव अक्सर कहते हैं कि विकास योजनाओं के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन के लिए मजबूत आर्थिक संसाधन आवश्यक हैं. इसके लिए उनकी नीति सरकारी खर्चों में कटौती करके अधिक से अधिक से राजस्व संग्रहित करने पर रही है. इसी क्रम में उन्होंने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को मिलाकर एक कर दिया. इस तरह के उन्होंने अन्य कदम भी उठाए हैं. डॉ मोहन यादव ने पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार के वार्षिक बजट का आकार लगभग दोगुना करके सात लाख करोड़ रुपयों के आसपास ले जाने का लक्ष्य भी सत्ता संभालने के तत्काल बाद तय कर लिया था. वे इसके अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से राज्य को और मजबूत बनाने तथा इन धरोहरों को संरक्षित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं. उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण, वैदिक घड़ी का लोकार्पण समेत ऐसे अनेक इस तरह के उदाहरण हैं. उन्होंने गायों के संरक्षण के लिए अनेक कार्य प्रारंभ किए. वे स्वयं मुख्यमंत्री निवास में गायों की प्रतिदिन पूजन और उनकी सेवा का दायित्व निभाते चले आ रहे हैं.

औद्योगिक विकास से नागरिकों को रोजगार के नए अवसर

भोपाल में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट और राज्य के अलग अलग हिस्सों में रीजनल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन करके लाखों करोड़ रुपयों के औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव भी आमंत्रित किए हैं. अनेक प्रस्ताव धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है. उनका मानना है कि औद्योगिक विकास से नागरिकों को रोजगार के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. उन्होंने राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे शांति के टापू के रूप में पहचाने जाने वाले इस राज्य की छवि बनी रहे.

केंद्र सरकार के मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लक्ष्य को हासिल करने में मध्यप्रदेश एक कदम आगे ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. दिसंबर माह में ही यह राज्य नक्सल मुक्त घोषित हो गया है. यह उपलब्धि भी डॉ मोहन यादव सरकार की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गयी है. दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनका ध्यान अब राज्य में अगले तीन वर्षों की कार्ययोजनाओं पर केंद्रित होता हुआ नजर आ रहा है. वे सडक, बिजली, ढ़ांचागत सुविधाओं के विस्तार, ऊर्जा के गैरपरंपरागत स्त्रोतों के दोहन, कृषि, सिंचाई और अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए दिखायी दे रहे हैं.

मध्यप्रदेश से नक्सलियों का हुआ खात्मा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालाघाट में पुनर्वास से पुनर्जीवन के अंतर्गत आयोजित नक्सलियों के आत्मसमर्पण कार्यक्रम में कहा कि-

- प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अब पूर्णतः नक्सल-मुक्त है.
- 42 दिनों में 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, रु. 7.75 करोड़ इनामी माओवादी नेटवर्क पूरी तरह ढहा.
- एमएमसी ज़ोन के सभी सूचीबद्ध सशस्त्र नक्सली या तो समाप्त कर दिए गए हैं या सरेंडर कर चुके हैं, प्रदेश में अब एक भी सक्रिय कैडर नहीं बचा.
- बालाघाट, मंडला और डिंडोरी – तीनों जिले नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की मुख्यधारा में लौट आए हैं.

- हमारे 38 शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को हम कृतज्ञता के साथ नमन करते हैं.
- 2024-25 में 17 बड़ी मुठभेड़ हुईं, जिनमें एसीएम स्तर के 10 खतरनाक नक्सली ढेर हुए और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए.
- 50 पुलिस मित्रों और 1000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती ने इस पूरे ऑपरेशन को निर्णायक गति दी.
- हमारी नीति स्पष्ट है – जो आत्मसमर्पण करेगा उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, और जो हथियार उठाएगा उसके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करेगा.
- नक्सली हिंसा से प्रभावित इलाकों में स्थायी शांति स्थापित हो चुकी है, अब विकास कार्य तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के ऐतिहासिक निर्णय और नीतियों से प्रदेश में हुई परिवर्तन के नये दौर की शुरुआत

योजनाएँ एवं महत्वपूर्ण निर्णय

- किसानों के लिए भावान्तर योजना
- विश्व विद्यालयों के कुलपति को कुलगुरू का सम्मानजनक नामकरण
- पुलिस बैंड को प्रोमोट
- खुले में मॉस के वितरण पर रोक
- धार्मिक स्थल और अन्य स्थलों में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग
- परिवहन चेक पोस्ट बंद
- दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि
- सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उचित उपचार दिलाने राहगीर योजना. सहायता करने वाले को 25 हजार रुपये एवं सर्टिफिकेट
- परिवहन विभाग की सेवाओं को ऑनलाइन करने सारथी पोर्टल
- हर किसान के खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर किसानों को ऊर्जादाता बनाना
- शौर्य संकल्प योजना में प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह के लिए अलग से बटालियन का गठन.
- मध्यप्रदेश परिसीमन आयोग का गठन
- सभी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में अधिकतम 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि
- कोदो, कूटकी खरीदी के लिए मूल्य निर्धारित
- लाड़ली बहनों को दी जा रही राशि में वृद्धि. अब 1250 रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 1500 रुपये लाड़ली बहनों को
- मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 जारी
- सीएम राइज स्कूल को सांदीपनि विद्यालयों के रूप में विकसित किया गया.
- देहदान करने वालों को राजकीय सम्मान
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना.
- भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण
- 22 हजार पुलिस कर्मियों की नवीन नियुक्तियाँ
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनू योजना, दुधारू पशुओं और डेयरी इकाई के लिए ऋण सहायता.
- सिंहस्थ 2028 के लिए 5 हजार से अधिक होमगार्ड भर्ती
- मुख्यमंत्री अदम साहसिक कार्य पुरस्कार, रेस्क्यू टीम को 51 हजार रुपये का पुरस्कार
- गोकुल ग्राम और वृंदावन ग्राम योजना
- जनवरी 2026 तक मध्यप्रदेश को नक्सल मुक्त बनाना
- स्वास्थ्य संस्थानों में 46 हजार 491 नये पदों का श्रृजन
- वीर शहीदों के परिजन की आर्थिक सहायता 50-50 प्रतिशत राशि पत्नी और माता-पिता को देना.
- प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने गरीब कल्याण मिशन.
- युवाओं की शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन.
- किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन.
- महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन.
- 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केन्द्र और 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन प्रारंभ.

प्रोजेक्ट

- पीएम मित्र पार्क
- मुरैना में सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना-ग्रीन ऊर्जा उत्पादन एवं स्टोरेज की नई राह
- मुहासा-बाबई प्रोजेक्ट
- केन-बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी
- पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना को मंजूरी
- ताप्ती बेसिन मेगा रीचार्ज परियोजना के लिए मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच एमओयू
- रायसेन जिले में रेल कोच निर्माण
- उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
- रातापानी सैंचुरी टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित.
- पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरूआत
- भोपाल-इंदौर को मेट्रोपालिटियन सिटी बनाना
- 5 नवीन एयरपोर्ट का संचालन शुरू
- पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ
- ओरछा में भव्य श्रीराम राजा लोक के निर्माण के साथ अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर लोक निर्माण.
- इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का शुभारंभ.
- राज्य परिवहन निगम की पुनर्स्थापना और यात्री बसों का संचालन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन, 3 लाख से अधिक 6 लाख कपास उत्पादकों को लाभ.
- निवेश और औद्योगिक विकास का नया इकोसिस्टम, 18 नई नीतियों को मंजूरी.
- GIS, RIC, इंट्रेक्टिव सेशन एवं विदेश यात्राओं से रु. 32 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्त अधिक रोजगार सृजन.
- रु. 8.57 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर.
- एक वर्ष में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव लाने वाला देश का तीसरा राज्य बना मध्यप्रदेश.
- निवेश को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए एमपी इंवेस्ट पोर्टल 3.0 लॉन्च.
- 881 इकाइयों को भूमि आवंटन, 281 इकाइयों का भूमिपूजन और 141 इकाइयों का शुभारंभ.
- 26 औद्योगिक पार्क/क्लस्टर को मंजूरी, मौजूदा 33 औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयन

गरीब कल्याण, वंचित वर्ग का कल्याण

- मध्यप्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए गरीब कल्याण मिशन शुरु.
- इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ का भुगतान
- मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में 6.81 लाख जरूरतमंदों को 6430 करोड़ रुपये की सह संबल योजना में सम्मिलित
- दिव्यांगता और मृत्यु के आधार पर रु. 4 लाख सहायता राशि
- 56 लाख से अधिक जरूरतमंदों को रु. 4330 करोड़ की पेंशन
- जनजातीय कल्याण के लिए रु. 40,804 करोड़ का बजट प्रावधान
- तेंदूपत्ता संग्राहकों पारिश्रमिक रु. 3000 से बढ़कर रु. 4000 हजार
- प्रधानमंत्री वन-धन केंद्र योजना अंतर्गत 20 जिलों में 126 वन-धन केंद्र स्थापित
- पीएम जनमन योजनांतर्गत रु. 98.30 करोड़ और धरती आबा योजनांतर्गत रु. 401.56 करोड़ से लोकार्पण और शिलान्यास